VISION IAS

www.visionias.in

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1515)

Name of Candidate	Bharat Jai prakash Meena		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	160872
Center	online	Date	1/12/22

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

1. Explain the meaning of off-budget borrowings and its role in helping the government raise funds for various expenditures. Also, comment on its desirability. (150 words) 10

बजटेतर उधारी (ऑफ-बजट बॉरोइंग्स) का अर्थ स्पष्ट कीजिए और विभिन्न व्ययों के लिए धन जुटाने में सरकार की सहायता करने में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। साथ ही, इसकी वांछनीयता पर टिप्पणी कीजिए।

बजटेतर उधारी से तात्पर्य विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा बजट प्रदत्त धन कम पड़ने पर बाजार से स्वयं उधार लेने की प्रक्रिया से है।

उदा॰ - FCI द्वारा off-budget borrowing का CAG रिपोर्ट में जिक्र किया है।

भूमिका / महत्व

(1) सरकारी बजट से धन की कमी की पूर्ति करता है।

(2) सरकारी Hidden borrowing में शामिल

(3) सरकारी ऋण में शामिल न होने से राजस्व घाटा संतुलित रहता है।

(4) सरकारी व्यय में लोचशीलता प्रदान करती है।

वांछनीयता

① off - budget borrowing सरकारी लोक - लुभावन राजनीति को बढ़ावा देती है।

② आफ - बजट - उधारी के माध्यम से covid जैसी आपदा के प्रति तत्काल अनुक्रिया की जा सकती है।

③ आफ - बजट - उधारी सरकारी विभागों के कार्यक्रम को प्रभावी बनाती है।

भारत में बढ़ती आफ - बजट - उधारी को लेकर CAG ने चिंता जताई है क्योंकि इस पर संसद का नियंत्रण नहीं होता। इसलिये 15th F.C. ने fiscal Council के गठन का भी प्रस्ताव रखा है।

2. It is argued that genetically modified food crops are required to ensure food security of India. Examine in view of concerns regarding introduction of GM crops. (150 words) 10

यह तर्क दिया जाता है कि भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य फसलों की आवश्यकता है। जी.एम. फसलों की शुरुआत से संबंधित चिंताओं के आलोक में परीक्षण कीजिए।

GM फसले आनुवंशिक रूप से संशोधित फसले होती है। ब्राजील, मैक्सिको एवं अर्जेंटीना द्वारा GM - फसलों के उपयोग द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धी की गयी है। भारत में भी इन्हें अपनाने पर चर्चा होती रहती है।

प्रमुख चिंताएँ

① मानव स्वास्थ्य पर GM - फसलों के दीर्घकाल में प्रभाव का आंकलन नहीं।

② भारतीय कृषि की GM - फसल अपनाने पर विदेशी कंपनियों पर निर्भरता में वृद्धी होगी।

③ GM - फसलों के मृदा जीवाणु

एवं पर्यावरण पर भी -ve प्रभाव सामने आये है।
(eg - DMH-11)

④ GM- फसलें बड़े किसानों के ही अनुकूल हो सकती है क्योंकि इनसे उत्पादन लागत में वृद्धी होगी।

⑤ पेटेंट संबंधी समस्याएँ

⑥ GM- फसलों के विनियमन हेतु सुदृढ़ ढाँचे का अभाव

⑦ जैव- आवर्धन एवं संचयन की समस्या

भारत की बढ़ती आबादी, विदेशों में सफल प्रयोग तथा कृषि सुधारों के क्रियान्वयन हेतु द्वितीय हरित क्रांति के लिये GM फसल अपनाने पर विचार करना चाहिये।

3. India's price intervention policies to support its agricultural sector not only create a broken system but also complicate matters related to international trade rules. Critically discuss. (150 words) 10
अपने कृषि क्षेत्र का समर्थन करने के लिए भारत की मूल्य हस्तक्षेप नीतियां न केवल एक अक्षम व्यवस्था का निर्माण करती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों से संबंधित मामलों को भी जटिल बनाती है। समालोचनात्मक विवेचना कीजिए।

भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मूल्य सब्सिडी पर्यावरण एवं बाजार पर नकारात्मक प्रभाव के साथ - साथ WTO में भी विवादों को जन्म दे रही है।

समस्याएँ

① सरकार द्वारा प्रदत्त MSP के माध्यम से जल - गहन फसलों को प्रोत्साहन मिला है जिससे भौमजल - स्तर में कमी।

② सरकार के राजकोषीय व्यय में भी वृद्धि

③ रासायनिक खाद- बीज उपयोग को बढ़ावा जिससे भूमि व जल प्रदूषण तथा GHG उत्सर्जन में वृद्धि।

④ फसल विविधीकरण को हतोत्साहित

Don't write anything this margin (इस स्थान में कुछ ना लिखें)

(5) भारत में विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आर्थिक असमानता में वृद्धि।

(6) बिजली डिस्कॉम्स पर भार में वृद्धि

(7) MSP के कारण बाजार कीमतें प्रभावित तथा लोकलुभावन राजनीति का जरिया।

(8) USA, कनाडा द्वारा डी-मिनिमस के विरुद्ध MSP व्यवस्था को बताना।

(9) कई देशों के अनुसार MSP व्यवस्था भारत में खाद्यान्न निर्यात को प्रोत्साहित करती है।

भारत ने खाद्य-सुरक्षा एवं किसान आय बढ़ाने की दृष्टि से MSP को उचित ठहराया है परंतु, पर्यावरणीय एवं राजकोषीय प्रभाव का विश्लेषण की जरूरत है।

Don't write anything this margin (इस स्थान में कुछ ना लिखें)

4. India has an opportunity to become a leading global food supplier provided it has an efficient supply chain and the right marketing strategies. Elucidate. (150 words) 10

भारत के पास एक अग्रणी वैश्विक खाद्य आपूर्तिकर्ता बनने का अवसर है बशर्ते उसके पास एक कुशल आपूर्ति शृंखला और सही विपणन रणनीति हो। विशदीकरण कीजिए।

भारत में विश्व में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि, भूमि-विविधता एवं जनांनकीकिय लाभांश, अग्रणी खाद्य आपूर्तिकर्ता बनने का अवसर प्रदान करते है। परंतु, आपूर्ति शृंखला एवं विपणन रणनीति इसमें प्रमुख बाधा है।

प्रमुख चुनौतियाँ

(1) विपणन व्यवस्था में APMC का बोलबाला तथा एकाधिकार

(2) मध्यस्थों की लम्बी शृंखला

(3) राज्यों द्वारा मॉडल APLMC को न अपनाना।

(4) कोल्ड स्टोरेज एवं ware-houses का अभाव।

Don't write anything this margin (इस स्थान में कुछ ना लिखें)

⑤ उच्च Logistics cost का होना। (लगभग - 14%)

⑥ निम्न खाद्य - प्रसंस्करण का स्तर (लगभग - 15%)

<u>समाधान की रणनीति</u>

① कान्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रोत्साहन

② सहकारी कृषि को बढ़ावा

③ APMC में सुधार हेतु APLMC Act अपनाना।

④ forward link एवं backward link में जुड़ाव।

⑤ e-commerce को कृषि विपणन द्वारा, सुधार बाजार की व्यवस्था

कृषि समस्या के सुधार द्वारा किसानों की आय 2022 तक दोगुना कर, $ 5tn अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस स्थान में कुछ ना लिखें)

5. Land banks are increasingly gaining prominence in India to encourage land-use efficiency and enable economic growth. In this context, discuss the benefits of a land bank and state the concerns associated with it.

(150 words) 10

भूमि उपयोग दक्षता को प्रोत्साहित करने और आर्थिक वृद्धि को सक्षम बनाने के लिए भूमि बैंक भारत में तेजी से प्रमुखता प्राप्त कर रहे हैं। इस संदर्भ में, भूमि बैंक के लाभों तथा इससे संबंधित चिंताओं का उल्लेख कीजिए।

भारत में भूमि अधिग्रहण संबंधी चुनौतीयों एवं व्यापार सुगमता को प्रोत्साहन ~~करने~~ हेतु भूमि बैंक की स्थापना की जा रही है।

<u>लाभ</u>

① भूमि आपूर्ति में वृद्धि।

② अवसंरचना परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण आसान।

③ शहरों में Real estate क्षेत्र को प्रोत्साहन

④ Land tax प्राप्ति द्वारा शहरी निकायों का सुदृढीकरण

⑤ व्यापार सुगमता में वृद्धि

चिंताएँ

① राज्य - सरकारों द्वारा जल्दबाजी में स्थापना।

② भूमि - विवादों की अत्याधिक संख्या।

③ geo-tagging की धीमी प्रगति।

④ शहरों में भूमि खरीद में कालाधन।

⑤ वितरणमूलक न्याय एवं सामाजिक न्याय में बाधा

समाधान
- भूमि - सुधार
- स्वामित्व योजना
- space tech का use
- National Land Man. Authority को प्रोत्साहन

भूमि बैंकों को प्रोत्साहन द्वारा शहरी क्षेत्रों में Affordable housing तथा उद्योग स्थापना को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

6. Desertification has been described as one of the greatest environmental challenges of our time and climate change is making it worse. Discuss. (150 words) 10

मरुस्थलीकरण को वर्तमान समय की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है तथा जलवायु परिवर्तन इसे और बदतर बना रहा है। चर्चा कीजिए।

मरुस्थलीकरण से तात्पर्य शुष्क, अर्द्धशुष्क एवं उप-शुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण एवं गुणवत्ता ह्रास से है। इसरो की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का 29.77+ क्षेत्र मरुस्थलीकरण एवं भू-निम्नीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है।

सबसे बड़ी चुनौती क्यों है?

① कृषि पर 60-65+ आबादी की निर्भरता

② खाद्य - सुरक्षा

③ भूमि की कार्बन सिंक के रूप में क्षमता में कमी

④ निर्धनीकरण को बढ़ावा।

⑤ भूमि - अपरदन को भी बढ़ावा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जलवायु परिवर्तन इसे और भी बदतर कैसे बना रहा है?

① extreme weather events जैसे सूखा एवं बाढ़ की बारंबारता।

② मृदा अपरदन एवं मरुस्थलीकरण झारखंड, दिल्ली जैसे राज्यों तक फैल रहा है

③ जलवायु परिवर्तन के कारण मृदा की उत्पादकता में कमी के कारण मरुस्थलीकरण को प्रोत्साहन।

भारतीय प्रयास
- बॉन challenge पर प्रगति रिपोर्ट
- दिल्ली से gujrat ग्रीन वॉल का प्रस्ताव
- UNCCD पर हस्ताक्षर

मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु वनीकरण एवं सतत कृषि विकास तकनीकों को अपनाना चाहिये।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. In the context of intellectual property rights, discuss the advantages and disadvantages of releasing projects under an 'Open Source' license.

(150 words) 10

बौद्धिक संपदा अधिकारों के संदर्भ में, 'ओपन सोर्स' लाइसेंस के तहत परियोजनाओं को जारी करने के लाभ और हानियों पर चर्चा कीजिए।

बौद्धिक संपदा, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा व्यापक मानवीय हित से संबंधित नवाचार को बताता है

'ओपन सोर्स' लाइसेंस के तहत परियोजना, बिना किसी कीमत के आम-जनता के सुझावों हेतु खुली रहती है।

लाभ

① परियोजना में निहित कमियां उजागर होती है।

② व्यापक भागीदारी

③ परियोजना की सुरक्षा में वृद्धि के लिये जरूरी है।

④ बेहतर user experience को प्रोत्साहन

⑤ coding को बेहतर बनाती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

हानि :-

① अन्य व्यक्ति भी ऐसे prototype बनाने हेतु प्रेरित हो सकते है।

② cyber vulnerability को बढ़ा भी सकता है।

③ मालवेयर Attack हो सकता है।

④ विदेशों में क्रय विक्री तथा Deep wabe पर क्रय लीक होना।

⑤ Data के आधार पर users को target किया जा सकता है।

open source license तकनीकी नवाचार एवं सुरक्षा सुभेद्यता उजागर, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. "Indian space sector has been dominated by a single umbrella of government and government institutions." In light of the statement, discuss the significance of Indian Space Association in providing an impetus to space technology in India. (150 words) 10

"भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र पर सरकार की एकमात्र संस्था का प्रभुत्व रहा है।" इस कथन के आलोक में, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन प्रदान करने में भारतीय अंतरिक्ष संघ के महत्व की विवेचना कीजिए।

आजादी के पश्चात् से ही भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र पर ISRO के माध्यम से सरकार का ही नियंत्रण रहा है। सरकार ने स्पेस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने तथा वैश्विक बाजार में भूमिका बढ़ाने की दृष्टि से स्पेस क्षेत्र में बदलाव हेतु indian space Ass. की स्थापना की है।

महत्व

① भारत में अंतरिक्ष पर्यटन को प्रोत्साहित एवं विनियमित करेगा।

② space क्षेत्र में निवेश (FDI) को बढ़ावा देगा।

③ वैश्विक साझेदारों के साथ

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

व्यापक अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देगा।

(4) नई स्पेस कंपनियों के पंजीकरण एवं विनियमन हेतु umbrella संगठन के रूप में कार्य करेगा।

(5) ISRO एवं अन्य निजी कंपनियों हेतु बाजार के नीति - निर्माण का कार्य करेगा।

(6) ISRO एवं निजी क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा हेतु एवं सहयोग तथा समन्वय हेतु प्रोत्साहन

(7) वैश्विक space economy में भारत की संलग्नता बढ़ाने तथा भूमिका बढ़ाने का कार्य करेगा।

(8) गगनयान जैसे मिशनों हेतु guidelines निर्माण।

(9) वैश्विक मंचों पर नेतृत्व

PM मोदी के अनुसार ISpA भारत को स्पेस के क्षेत्र में अग्रणी बनाने हेतु 21th सदी का भारत बनाने में महत्वपूर्ण रहेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. Man and machine both have an important role in national security and making urban areas secure. In this context, discuss how technology is a major stakeholder in addressing the internal security challenges of India. (150 words) 10

राष्ट्रीय सुरक्षा और शहरी क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने में मानव और मशीन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संदर्भ में, चर्चा कीजिए कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में एक प्रमुख हितधारक है।

भारत के शहरी क्षेत्रों में बढ़ते अपराधों तथा सीमापार ड्रोन हमलों ने शहरी सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में तकनीक का महत्व उजागर किया है।

प्रमुख चुनौती व निपटने में महत्व

(1) शहरी क्षेत्रों में ड्रग व wild life trade का online क्रय - विक्रय

tech. - online सोशल मीडिया की निगरानी द्वारा रोकथाम

(2) शहरी critical infra पर विदेशी Attack

समाधान - साइबर क्षमता में वृद्धि करना तथा NCIIPC में (मानव संसाधन आपूर्ति कुशल करना)

③ सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन से नोट एवं हथियारों की तस्करी

<u>समाधान</u> - इजराइल की हीरोन UAV की तैनाती द्वारा निगरानी

④ डाटा चोरी, cyber stalking वित्तीय फ्रॉड, रैनसमवेयर आदि की चुनौती

<u>समाधान</u> - शहरी पुलिस में साइबर सुरक्षा कमांड स्थापित करना।

⑤ सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्रों में तकनीक एवं ड्रोन के माध्यम से निगरानी एवं Attack करना।

⑥ तकनीक के माध्यम से सैन्य बलों की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है।

सुरक्षा में तकनीक का उपयोग बढ़ाने हेतु भारत सरकार ने Drones Regulation guidelines द्वारा शहरी व राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोत्साहन किया है।

10. National Security Guard (NSG) has emerged as a formidable force equipped to handle various manifestations of terrorism. Discuss the mandate and achievements of this force. (150 words) 10

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) एक पराक्रमी बल के रूप में उभरा है जो आतंकवाद के विभिन्न रूपों से निपटने के लिए सुसज्जित है। इस बल के अधिदेश और उपलब्धियों की विवेचना कीजिए।

NSG भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रथम पंक्ति एवं प्रथम अनुक्रियाकर्ता बल की भूमिका निभाता है। NSG को आतंकी गतिविधियों से निपटने हेतु विशेष रूप से सुसज्जित किया गया है।

<u>अधिदेश</u> -

① आतंकी घटनाओं की प्रथम अनुक्रिया करना।

② सीमापार आतंकी कैंपों को समाप्त करना

③ आतंक से निपटने हेतु पड़ोसी देशों के सैन्य बलों के साथ सहयोग बढ़ाना

④ आतंकवाद से निपटने हेतु बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के सैन्यबलों को प्रशिक्षण।

Don't write anything this margin (इस स्थान में कुछ ना लिखें)

(5) आतंकवादियों द्वारा प्लेन Hijack की स्थिति में निपटना।

उपलब्धियाँ

(1) मुम्बई हमले के पश्चात् अनेक हमलों को पूर्व में ही पहचानकर निष्क्रिय किया है।

(2) उरी, पठानकोट जैसे हमलों की जाँच में NIA के साथ सहयोग द्वारा पूर्णता प्रदान करना।

(3) सीमापार आतंकी कैम्प एवं surgical strikes को अंजाम देना।

(4) आतंकीयों से निपटने हेतु कश्मीर घाटी में operation - All out का क्रियान्वयन करना।

NSG आज भी आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में अहम भूमिका निभाकर, राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान दे रहा है।

Don't write anything this margin (इस स्थान में कुछ ना लिखें)

11. What do you understand by asset monetisation? Why is it needed in India? In this context, discuss the issues that need to be addressed for the National Monetisation Pipeline to succeed. (250 words) 15

परिसंपत्ति मुद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है? इस संदर्भ में, उन मुद्दों पर चर्चा कीजिए जिन्हें राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के सफल होने के लिए समाधान करने की आवश्यकता है।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण से तात्पर्य पहले से निर्मित परिसंपत्ति पर स्वामित्व बनाये रखते हुये संचालन एवं क्रियान्वयन का ~~संपत्ति~~ अधिकार किसी निजी कंपनी को सौंपकर, एकमुश्त धनराशि प्राप्त करने से है।

आवश्यकता

(1) भारत में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिये

(2) आधारभूत संरचना क्षेत्र में पूंजी की कमी को पूरा करने के लिये।

(3) पूर्व - निर्मित परिसंपत्ति के बेहतर संचालन एवं क्रियान्वयन ~~के~~ हेतु

(4) सरकारी हस्तक्षेप, सार्वजनिक

क्षेत्र में कम करने तथा अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये।

⑤ राजकोषीय घाटा की पूर्ति

भारत सरकार ने परिसंपत्ति मुद्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुये राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के माध्यम से भविष्य की रूपरेखा तैयार की है-

मुद्दे

① सिर्फ Brownfield project ही शामिल है।

② मौद्रीकरण हेतु एक्सप्रेस-वे का अभाव।

③ निजी क्षेत्र की अरूचि

④ उच्च बोली कीमत

⑤ सामाजिक न्याय प्राप्ति में बाधा के रूप में देखा जाना।

1515
VISION IAS™

⑥ सार्वजनिक परिसंपत्ति का उपयोग करना महंगा हो सकता है।

⑦ Logistics cost में वृद्धि की चुनौती

समाधान

① पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया को प्रोत्साहन

② सार्वजनिक नीलामी एवं ओदेशों में सत्यनिष्ठा रीति अपनाना।

③ National ~~Policy for~~ Programe ~~and Project~~ for project management and policy framework अपनाना।

④ निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन हेतु PPP मॉडल में सुधार करना तथा केलकर समिति की अनुसंशा मानना

⑤ सेवा उपयोग कीमतों को विनियमित करने हेतु ढाँचा निर्माण करना।

NMP, भारत में NIP एवं PM-गतिशक्ति जैसी योजनाओं हेतु धन-आपूर्ति के लिये सहायक के रूप में कार्य करेगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. What is social stock exchange (SSE)? Discuss the need for setting up of SSEs and key challenges in their effective implementation. (250 words) 15
सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) क्या है? SSEs की स्थापना की आवश्यकता और उनके प्रभावी कार्यान्वयन में विद्यमान प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

सोशल स्टाक एक्सचेंज, सामाजिक उद्यमों में निवेश हेतु गैर लाभकारी संगठन एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा वित्तीयन हेतु एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है।

आवश्यकता

① ESG funds को प्रोत्साहित करने के लिये।

② शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा प्रदायगी में सरकार के सहायक के रूप में

③ सामाजिक अवसंरचनाओं हेतु वित्त की कमी पूरा करने के लिये

④ social impact investors हेतु सामाजिक रूप से लाभकारी उद्यमों की पहचान हेतु

1515
VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⑤ शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाकर सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिये।

⑥ CSR के उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिये।

चुनौतियाँ

① SSE के क्रियान्वयन हेतु अनुभव का अभाव

② SSE के कार्यकाल हेतु मानकों का अभाव

③ स्थानीय निकायों में व्याप्त भ्रष्टाचार

④ निवेशक एवं संबंधित सिविल सोसायटी के मध्य डाटा आदान-प्रदान का अभाव।

⑤ संगठनों के प्रति बढ़ता अविश्वास एवं अरुचि।

⑥ धन के दुरुपयोग रोकने हेतु निगरानी ढाँचे का अभाव

समाधान

① SSE के कार्यान्वयन हेतु वैश्विक मानकों को अपनाना

② ESG funds को प्रोत्साहन देना।

③ CSR को SSE से जोड़ना

④ निवेशक एवं सामाजिक अवसंरचना प्रदाताओं के मध्य अच्छा आदान - प्रदान

⑤ राजनीतिक दलों एवं धार्मिक संस्थानों का निवेश (SSE में) करने से रोकना (SEBI technical group)

भारत में SSE के क्रियान्वयन को सफलतापूर्वक संचालित करने हेतु सिंगापुर एवं आस्ट्रेलिया के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिये।

13. In the context of India, highlight the importance of agriculture extension. What are the challenges faced in provisioning of agriculture extension services? How does the National Mission on Agricultural Extension & Technology (NMAET) address these issues? (250 words) 15

भारत के संदर्भ में, कृषि विस्तार के महत्व पर प्रकाश डालिए। कृषि विस्तार सेवाओं के प्रावधान में सामना की जाने वाली चुनौतियां कौन-सी हैं? कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (NMAET) इन मुद्दों का कैसे समाधान करता है?

भारत में बढ़ती जनसंख्या एवं खाद्यान्न की बढ़ती मांग को देखते हुये कृषि - विस्तार आवश्यक है।

महत्व

- → बेरोजगारी दूर करने में
- → समावेशी विकास में
- → कोविड से उभरने में
- → ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन
- → महिला सशक्तिकरण में
- → उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि

प्रमुख -चुनौतियाँ

① पर्यावरण संरक्षण एवं आर्थिक विकास हेतु कृषि विस्तार का टकराव।

② कृषि विस्तार के कारण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की समस्या

③ कृषि की निम्न उत्पादकता

④ 86+ किसान लघु एवं सीमांत किसान है। (कृषि जनगणना 2015-16)

⑤ उद्योगों की स्थापना के कारण भू-उपयोग परिवर्तन

⑥ वनीकरण हेतु राष्ट्रीय नीति के अनुसार 33% भूमि पर वनावरण का प्रावधान

⑦ जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रतिबद्धताएँ

⑧ फसल अवशेष प्रबंधन व पराली दहन

कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर मिशन:-

① महिला-अनुकूल मशीनों का विकास किया जा सकता है।

② मशीनीकरण के द्वारा फसल

प्रबंधन बेहतर दक्षता के साथ।

③ जल-उपयोग दक्षता को प्रोत्साहन

④ भूमि का उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि

⑤ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से निपटने में मदद मिलेगी क्योंकि उसके द्वारा बेहतर फसल अवशेष प्रबंधन किया जा सकता है।

⑥ किसानों की आय में वृद्धि को प्रोत्साहन

⑦ कृषि में Research & Dev. तथा नवाचार को प्रोत्साहन

कृषि विस्तार द्वारा, पर्यावरण समस्या के समाधान के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बढ़ाकर, भारत के $5 tn के सपने को भी पूरा करने में मदद मिलेगी।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. Clearly delineate the 'employment problem' that India currently faces. Also, explain the fundamental reasons behind existence of this problem. (250 words) 15

भारत वर्तमान समय में जिस 'रोजगार समस्या' का सामना कर रहा है, उसे स्पष्ट रूप से निरुपित कीजिए। साथ ही, इस समस्या के अस्तित्व के मूल कारणों की व्याख्या कीजिए।

ILO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में पिछले 45 वर्ष में अधिकतम बेरोजगारी देखी गयी है। Covid-19 जनित लाकडाउन से आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने तथा उद्योगों के बंद होने के कारण समाज का कमजोर वर्ग नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है जिसे प्रवासी श्रमिकों की समस्या से भी समझा जा सकता है।

मूल कारण

① LPG सुधारों के पश्चात् से ही रोजगारविहीन संवृद्धि एवं अल्परोजगार की स्थिति
[विकास दर - 7-8%, रोजगार दर - 3-4%]

② कृषि में व्याप्त मौसमी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी

③ शिक्षित बेरोजगारी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

④ श्रम का अनौपचारीकरण, अल्प-रोजगार एवं अनियमितीकरण की समस्या।

⑤ Covid-19 जनित आपूर्ति श्रृंखला संबंधित चुनौती।

⑥ श्रम गहन उद्योगों के स्थान पर पूंजीगहन उद्योगों को प्रोत्साहन

⑦ श्रम सुधारों का अभाव एवं श्रम कानूनों में व्याप्त जटिलता

⑧ व्यापार सुगमता का अभाव

समाधान

① श्रम संहिताओं को लागू करना

② सामाजिक-सुरक्षा का विस्तार करना।

③ श्रमबल में महिला-भागीदारी को प्रोत्साहन

④ श्रम एवं अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण

⑤ MSME को प्रोत्साहन

⑥ श्रम गहन उद्योगों को प्रोत्साहन

(7) कृषि के बढ़ते महिलाकरण के मद्देनजर, महिलानुकूल कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहन

किये गये प्रयास

(1) e-श्रम पोर्टल
(2) make in India विनिर्माण प्रोत्साहन
(3) श्रम - संहिता निर्माण
(4) PM - किसान निधि
(5) कृषि में मशीनीकरण पर राष्ट्रीय मिशन
(6) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से श्रम मैपिंग
(7) स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा।

भारत में बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु व्यापक कृषि सुधार की आवश्यकता है जिससे बेरोजगारी से निजात मिले तथा समावेशी विकास हो सके।

15. Although steps have been taken for integrating the dispersed logistics activities of maritime trade, much more needs to be done to make India a maritime powerhouse. Discuss. (250 words) 15
हालांकि समुद्री व्यापार की बिखरित लॉजिस्टिक गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, फिर भी भारत को एक समुद्री पावरहाउस बनाने के लिए और भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए।

भारत अपने कुल व्यापार का मात्रा की दृष्टि से 90% तथा कीमत - 70% व्यापार समुद्री मार्गों के माध्यम से ही करता है।

प्रमुख कदम

(1) मेजर port Authority bill के माध्यम से मेजर पोर्ट्स के प्रशासन में सुधार
(2) Landlord port model का प्रोत्साहन
(3) National monetization pipeline के माध्यम से मौद्रीकरण एवं क्रियान्वयन तथा संचालन में सुधार
(4) White shipping पर IMO के दिशा-निर्देशों का पालन
(5) 2012-14 में ports क्षमता

700-800 mn tones से बढ़ाकर 1100 mn tones करना

6. पोर्ट्स पर turnaround समय 96 hr से 64 hr करना

7. नई Logistics नीति का प्रावधान

8. ports पर multi-model Logistics parks की स्थापना

समस्याएँ

1. समुद्री व्यापार हेतु कंटेनर के लिये विदेशों पर निर्भरता

2. बड़े wide shipping जहाजों की निर्माण क्षमता का अभाव

3. समुद्री piracy

4. सिंगापुर एवं china की तुलना में Logistics cost GDP की 14%

5. turnaround time भी वैश्विक औसत से ज्यादा

6. समुद्री व्यापार संबंधी विवादों को सुलझाने हेतु ढाँचे का अभाव

समाधान

1. सशक्त -पोर्ट्स व्यवस्था

2. IRNSS द्वारा समुद्री यातायात की निगरानी

3. रक्षा जहाज निर्माण के साथ goa shipyard में commercial जहाज एवं कंटेनर निर्माण को प्रोत्साहन

4. Logistics cost कम करने हेतु e-clearance को प्रोत्साहन

5. ports की क्षमता वृद्धि

6. नये ports का निर्माण जिससे major ports पर दबाव कम हो सके।

समुद्री व्यापार सुगमता के द्वारा भारत वर्तमान स्थित अनेक Free trade Agreements का लाभ उठाकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भूमिका वृद्धि कर सकता है।

16. Accounting for natural capital and ecosystem services is crucial to understand the link between the economy and environment. Discuss with specific references to India's initiatives in this regard. (250 words) 15

अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के मध्य संबंध को समझने के लिए प्राकृतिक पूंजी और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए लेखांकन महत्वपूर्ण है। इस संबंध में भारत द्वारा की गयी पहलों के विशिष्ट संदर्भ के साथ चर्चा कीजिए।

आर्थिक विकास एवं पर्यावरण के मध्य संतुलन भारत एवं अन्य विकासशील देशों की प्रमुख दुविधा है।

भारत के सांख्यिकी मंत्रालय ने प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा जलवायु जोखिम से निपटने हेतु पर्यावरण प्रदत्त सेवाओं के मौद्रिक मूल्यांकन हेतु प्राकृतिक पूंजी लेखांकन को बढ़ावा देने हेतु SEEA को प्रोत्साहित किया है।

SEEA का महत्व

1. जलवायु परिवर्तन संबंधी नीति-निर्माण में सहायक
2. जलवायु जोखिम का मूल्यांकन

3. पेरिस Agree. एवं वैश्विक प्रतिबद्धता के पालन में सहायक
4. पर्यावरण संबंधी जागरूकता को प्रोत्साहन
5. देशज समुदायों का महत्व स्थापित किया जा सकेगा।

भारतीय पहलें

1. उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने gross Domestic product के समान gross environment product (GEP) की गणना प्रारंभ की है।
2. प्रकृति आधारित समाधानों को बढ़ावा देने का आह्वान किया है।
3. system for environmental ~~econo~~ economic ecosystem services and Accounting को प्रोत्साहन।
4. सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में

डैशबोर्ड आधारित मानिटरिंग

(4) ESG funds में निवेश को प्रोत्साहन।

(5) अवसंरचना projects हेतु environment impact assessment का प्रावधान।

(6) SDG - India Index के माध्यम से राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा

प्राकृतिक पूंजी एवं पारिस्थितिकी सेवा लेखांकन हेतु वैश्विक मानकों की UNFCCC पर चर्चा द्वारा वैश्विक मानक निर्धारण की जरूरत है जिससे पेरिस लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकेगी।

17. Rapid and unplanned urbanisation accompanied by population growth have increased both the risk and impact of natural disasters. Discuss the statement along with adequate measures to address the relevant concerns in India. (250 words) 15

जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ तीव्र और अनियोजित शहरीकरण ने प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम और प्रभाव दोनों को बढ़ा दिया है। भारत में विद्यमान प्रासंगिक चिंताओं के निवारण हेतु यथोचित उपायों के साथ इस कथन की व्याख्या कीजिए।

यूनाइटेड नेशन्स के अनुसार 2050 तक भारत की 65+ आबादी शहरों में निवास करेगी। हाल ही में मुम्बई, चेन्नई, बेंगलुरु में शहरी बाढ़ की घटनाओं ने भारतीय शहरों की आपदाओं के प्रति सुभेद्यता को दर्शाया है जिसे बढ़ते शहरीकरण ने और भी बढ़ाया है।

प्रमुख चिंताएँ -

(1) urban Heat islands का निर्माण।

(2) अत्यधिक कंक्रीटीकरण, जो कि शहरी बाढ़ को प्रोत्साहित कर रहा है।

(3) शहरों में प्राचीन जल संरचनाओं का अतिक्रमण

बैंगलुरु में 1960 → 250 झीलें वर्तमान में 10)

④ शहरों में कच्ची एवं अनियोजित बस्तियाँ

⑤ जल-निकास प्रणाली का अवरुद्ध होना तथा क्षमता का अभाव

⑥ अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौती

⑦ शहरी निकायों के पास वित्तीयन एवं क्षमता अभाव

⑧ तटीय शहरों में तटीय अपरदन एवं बढ़ता समुद्री जल स्तर (IPCC रिपोर्ट)

समाधान

① cities climate Action framework अपनाना।

② स्पान्ज सिटी निर्माण

③ शहरी वनीकरण को प्रोत्साहन

④ पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री अपनाना।

⑤ urban local body में 15th वित्त आयोग की अनुशंसा मानना।

⑥ शहरी निकायों हेतु waste to energy corporation of India Ltd. की स्थापना (नीति-आयोग)

⑦ शहरी निकायों हेतु municiple bonds जारी करने की अनुमति

किये गये प्रयास

① मुम्बई, चेन्नई में बाढ़ चेतावनी हेतु IN FLOWS की स्थापना

② CRZ नियम

③ शहरी निकायों में सुधार

④ नगरी वन योजना

भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया को समावेशी एवं धारणीय बनाने तथा पर्यावरण अनुकूल बनाने हेतु

18. National Hydrogen Mission can be a game changer for India's rising energy demands. Comment. (250 words) 15
भारत की बढ़ती ऊर्जा मांगों के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन एक गेम चेंजर हो सकता है। टिप्पणी कीजिए।

अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान के अनुसार भारत विश्व के 3rd सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक है परंतु, प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग की दृष्टि से 106th है। बढ़ती जनसंख्या एवं आर्थिक विकास के फलस्वरूप ऊर्जा मांग लगातार बढ़ रही है।

भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग को देखते हुये सरकार ने बजट - 2021 में राष्ट्रीय H_2 मिशन की घोषणा की है।

महत्व

- → स्वच्छ ईंधन
- → नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत
- → वायु प्रदूषण से निपटने में मददगार
- → ऊर्जा बॉस्केट में 9% का योगदान 2030 तक 15+ करने हेतु महत्वपूर्ण

बढ़ती मांग पूरी करने में योगदान

① वाहनों हेतु स्वच्छ ईंधन की बढ़ती मांग तथा crude oil पर निर्भरता कम करेगा।

② स्वच्छ एवं दक्ष ईंधन है जो कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है।

③ भारत की स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में महत्वपूर्ण योगदान।

④ जल के अपघटन द्वारा आसान प्राप्ति

⑤ electric vehicle एवं rare earth metals पर निर्भरता कम कर सकता है।

चुनौतियाँ

① H_2 उत्पादन जीवाश्म ईंधन से

② विस्फोटक प्रकृति

③ ट्रांसपोर्ट आसान नहीं

④ महंगा है।

भारतीय प्रयास

1. राष्ट्रीय H_2 मिशन
2. National H_2 एलायंस
3. H_2 fuel cell को प्रोत्साहन
4. सोलर ऊर्जा द्वारा H_2 उत्पादन को प्रोत्साहन
5. H-CNG बसों का दिल्ली में संचालन

H_2, निश्चित ही भारत की ऊर्जा मांग को पूरी करते हुये 2070 तक भारत को Net zero emitter बनाकर वैश्विक प्रतिबद्धता पूरी करने में लाभकारी रहेगा।

19. Despite geo-strategic instability of its region and a keen awareness of the cyber threat it faces, India has made only 'modest progress' in developing its policy and doctrine for cyberspace security. Critically examine.

(250 words) 15

अपने क्षेत्र की भू-रणनीतिक अस्थिरता और इसके समक्ष विद्यमान साइबर खतरों के संबंध में व्यापक जागरूकता के बावजूद, भारत ने साइबरस्पेस सुरक्षा के लिए अपनी नीति और सिद्धांत विकसित करने में केवल 'साधारण प्रगति' की है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

हाल ही में मुम्बई पावरग्रिड पर हुये साइबर हमले तथा CERT-IN की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में साइबर हमलों में 300% वृद्धि ने साइबर सुरक्षा की जोखिम को उजागर किया है।

भारतीय प्रयास

1. National cyber security policy, 2013
2. CERT-IN का निर्माण
3. NTRO की स्थापना
4. Indian cyber crime Co-ordination Committee (IC_4) की स्थापना
5. National cyber crime Co-ordinator (NC_3) की स्थापना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(6) Crime and criminal tracking Network system (CCTRNS) की स्थापना

(7) साइबर वालंटियर प्रोग्राम

(8) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना

(9) NCIIPC

मूल्यांकन

(1) साइबर सुरक्षा नीति, 2013 वर्तमान साइबर हमलों से निपटने के अनुकूल नहीं है क्योंकि वर्तमान में साइबर हमलों की प्रकृति में व्यापक बदलाव आया है।

(2) वर्तमान में फिशिंग, फार्मिंग, back door entry, cyber stalking, Honey trap आदि से निपटने में वर्तमान ढाँचा अपर्याप्त है।

(3) साइबर सुरक्षा नीति, मानव ~~संसा~~ संसाधन विकास

1515
VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

की दृष्टि से सफल नहीं रही

(4) केन्द्र-राज्य अविश्वास के कारण भय भेयर न होना।

(5) नागरिक जागरूकता का अभाव।

(6) सरकारी एजेंसियों के मध्य सहयोग एवं समन्वय का अभाव।

(7) साइबर सुरक्षा उपकरणों हेतु विदेशों पर अभी भी निर्भरता है।

भारत को साइबर सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु '5 eye' समूह के साथ सहयोग बढ़ाने तथा साइबर सुरक्षा उपकरणों की आत्मनिर्भरता पर फोकस करना चाहिये।

20. Developmental interventions alone cannot play a defining role in the resolution of existing and protracted internal conflicts in various parts of India within a reasonable time frame. Discuss. (250 words) 15

भारत के विभिन्न हिस्सों में व्याप्त और दीर्घकाल से जारी आंतरिक संघर्षों को उचित समय सीमा के भीतर हल करने में केवल विकासात्मक हस्तक्षेप एक निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकते हैं। चर्चा कीजिए।

भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अनेक आंतरिक संघर्ष - नागालैण्ड, बोडोलैण्ड एवं मिजो समुदाय के साथ-साथ नक्सली एवं माओवादी जैसी Left wing extremism की समस्या व्याप्त है।

भारत सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकासात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से इनके समाधान का प्रयास किया है।

प्रमुख प्रयास -

① Aspirational District Program
② 6th अनुसूची के तहत संरक्षण
③ inner Line permit का प्रावधान।

④ Art - 371 में निहित विशेष उपबंध
⑤ स्वयं - प्रसंस्करण उद्योगों का प्रोत्साहन
⑥ कनेक्टिविटी को बढ़ावा
⑦ शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ
⑧ केन्द्र सरकार की योजनाओं में 10% तक विनियोजन का प्रावधान।

इन सभी प्रयासों के बावजूद भी समस्या समाधान में चुनौतियाँ व्याप्त है-

कारण

① व्याप्त आंतरिक संघर्ष का कारण विकासात्मक के अलावा नृजातीय पहचान का मुद्दा है।
② AFSPA के माध्यम से सैन्य बलों की कार्यवाही का विरोध
③ शत्रु देशों द्वारा विद्रोही ग्रुपों की फंडिंग
④ निरक्षरता एवं जागरूकता का अभाव।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

समाधान

① विभिन्न जनजातीय समूहों के साथ वार्ता करना।

② जनजातीय प्रथा एवं रूढ़ियों की सुरक्षा के साथ विकासात्मक प्रोत्साहन।

③ Border disputes का समाधान करना।

④ N-E Zonal council के माध्यम से आपसी संवाद को प्रोत्साहन।

⑤ नक्सलवाद/ माओवाद हेतु SAMADHAN रणनीति अपनाना।

⑥ मजबूर एवं मजबूत समूहों की पहचान कर भिन्न -2 कार्यवाही दृष्टिकोण।

⑦ सैन्य बलों की कार्यवाही में स्थानीय पुलिस का सहयोग लेना।

भारत की नृजातीय विविधता एवं भौगोलिक चुनौतियों के समाधान हेतु राज्य- सरकारों के मध्य सहयोग एवं समन्वय भी जरूरी है।